

संपादकीय

गडकरी ने की राहत देने की बात

के द्वारा संदर्भ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 27 जून को हाइके पर यात्रा करने वाले लोगों की परेशनियों को देखते हुए और देकर कहा कि यह संदर्भ अच्छी हालत में नहीं है, तो राजमार्ग एवं सेवोंसे को टोल नहीं लगाना चाहिए। टोल तभी वसूला जाना चाहिए, जब बेहतरीन गुणवत्ता वाली सड़कें प्रदान की जाएं। गंगुले और कीचड़ वाली घटिया सड़कों के लिए भी टोल वसूलने से जनता में अक्रोश पैदा हो सकता है और आपको लोगों की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद 28 जुलाई को नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक प्रस्तुति दिखायी कि जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की मांग की है, जो इस समय 18 प्रतिशत है। इस पत्र में श्री गडकरी ने बताया है कि हाल ही में नागरुक डिजिटल लाइफ इंडेप्रेस कारोबारिन इंस्टाइंज यूनियन ने बीमा उद्योग से संबंधित मुद्दों पर एक ज्ञान प्रस्तुत करके उनसे मुख्य रूप से जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की मांग की है। श्री गडकरी के अनुसार यूनियन का मानना है कि जो व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा प्रीमियम और चिकित्सा बीमा प्रीमियम अदा करता है, उस पर यह टैक्स नहीं लगाना चाहिए। जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है। अतः आपसे अनुरोध है कि जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बोझ के समान है। ध्यान रहे कि नेशनल इंडेप्रेस अकादमी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 73 प्रतिशत लोगों के पास चिकित्सा बीमा नहीं है। इतना ही नहीं, देश में चिकित्सा बीमा का प्रीमियम रहना 25 से 30 प्रतिशत लोग अपने चिकित्सा बीमा का नवीनीकरण नहीं करता पाते।

नेशनल इंडेप्रेस अकादमी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 73 प्रतिशत लोगों के पास चिकित्सा बीमा नहीं है। इतना ही नहीं, देश में चिकित्सा बीमा का प्रीमियम 25 से 30 प्रतिशत लोग अपने चिकित्सा बीमा का नवीनीकरण नहीं करता पाते। बुजुर्गों को चिकित्सा बीमा के प्रीमियम के लिए प्रतिवर्ष 12 से 15 हजार रुपये देने पड़ते हैं जो महांग होने के कारण उनके लिए संभव नहीं होता। ऐसे में चिकित्सा बीमा लेने वाले लोगों से प्रीमियम पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूल करना सरकार के लिए नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतः जहां खरां राहत मिलेगी, वहाँ चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी समाप्त करने तय दिए हुए प्रीमियम पर आयकर में 100 प्रतिशत छूट देने से लोगों में चिकित्सा बीमा लेने का रुझान बढ़ेगा। इससे उनके स्वास्थ्य में मदद मिलेगी।

अभिमत आजाद सिपाही

1984 से 88 तक संयुक्त राष्ट्र में इसराईल के संघटन के रूप में उनके कार्टिकाल ने उन्हें न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में याहूदियों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने और मजबूत करने में मदद की। तेल अवीव के बाद न्यूयॉर्क में याहूदियों की सबसे बड़ी आबादी है और यह दुनिया का सबसे ग्रामावासी शहर है। विशेषज्ञों ने यूएस में इसराईल लॉबी को एक ऐसी संस्था के रूप में उद्धृत किया है, जो अमेरिका विदेश नीति को इसराईल के हितों के साथ जोड़ती है।

इसराईल के लिए हार के समान होगा युद्धविराम

सङ्केत नक्काश

टारनटो की फिल्म जैगे अनवेंड का क्रूर यथार्थवाद शायद पेट के कमज़ोर लोगों को भी उटारी करता है। अमेरिका के सुदूर दक्षिण में रहने वाला एक श्वेत बागान मालिक अपने तिवारिं स्तर में सोंपे कर बैठा हुआ 2 मजबूत गुलामों को लड़ते हुए देखता है, दोनों कम से कम तब तक लड़ते हैं जब तक कि उन्हें से एक दूसरे की आंखें नहीं निकाल लेता। बाहर, भड़ियों से भी बड़े आकार के भूखे कुत्तों का एक बूँद एक गुलाम पर छोड़ दिया जाता है जो पेड़ पर चढ़ने की व्यवहार कोशिश करता है।

लीवर जंगल में विलाप करते हुए कहता है, जैसे आवारा लड़कों के लिए प्रीमियम अदा करता है, उस पर यह टैक्स नहीं लगाना चाहिए। जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है। अतः आपसे अनुरोध है कि जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बोझ के समान है। ध्यान रहे कि नेशनल इंडेप्रेस अकादमी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 73 प्रतिशत लोगों के पास चिकित्सा बीमा नहीं है। इतना ही नहीं, देश में चिकित्सा बीमा का प्रीमियम 25 से 30 प्रतिशत लोग अपने चिकित्सा बीमा का नवीनीकरण नहीं करता पाते। बुजुर्गों को चिकित्सा बीमा के प्रीमियम के लिए प्रतिवर्ष 12 से 15 हजार रुपये देने पड़ते हैं जो महांग होने के कारण उनके लिए संभव नहीं होता। ऐसे में चिकित्सा बीमा लेने वाले लोगों से प्रीमियम पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूल करना सरकार के लिए नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतः जहां खरां राहत मिलेगी, वहाँ चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बोझ के समान है। ध्यान रहे कि नेशनल इंडेप्रेस अकादमी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 73 प्रतिशत लोगों के पास चिकित्सा बीमा नहीं है। इतना ही नहीं, देश में चिकित्सा बीमा का प्रीमियम 25 से 30 प्रतिशत लोग अपने चिकित्सा बीमा का नवीनीकरण नहीं करता पाते। बुजुर्गों को चिकित्सा बीमा का प्रीमियम के लिए प्रतिवर्ष 12 से 15 हजार रुपये देने पड़ते हैं जो महांग होने के कारण उनके लिए संभव नहीं होता। ऐसे में चिकित्सा बीमा लेने वाले लोगों से प्रीमियम पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूल करना सरकार के लिए नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतः जहां खरां राहत मिलेगी, वहाँ चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बोझ के समान है। ध्यान रहे कि नेशनल इंडेप्रेस अकादमी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 73 प्रतिशत लोगों के पास चिकित्सा बीमा नहीं है। इतना ही नहीं, देश में चिकित्सा बीमा का प्रीमियम 25 से 30 प्रतिशत लोग अपने चिकित्सा बीमा का नवीनीकरण नहीं करता पाते। बुजुर्गों को चिकित्सा बीमा का प्रीमियम के लिए प्रतिवर्ष 12 से 15 हजार रुपये देने पड़ते हैं जो महांग होने के कारण उनके लिए संभव नहीं होता। ऐसे में चिकित्सा बीमा लेने वाले लोगों से प्रीमियम पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूल करना सरकार के लिए नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतः जहां खरां राहत मिलेगी, वहाँ चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बोझ के समान है। ध्यान रहे कि नेशनल इंडेप्रेस अकादमी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 73 प्रतिशत लोगों के पास चिकित्सा बीमा नहीं है। इतना ही नहीं, देश में चिकित्सा बीमा का प्रीमियम 25 से 30 प्रतिशत लोग अपने चिकित्सा बीमा का नवीनीकरण नहीं करता पाते। बुजुर्गों को चिकित्सा बीमा का प्रीमियम के लिए प्रतिवर्ष 12 से 15 हजार रुपये देने पड़ते हैं जो महांग होने के कारण उनके लिए संभव नहीं होता। ऐसे में चिकित्सा बीमा लेने वाले लोगों से प्रीमियम पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूल करना सरकार के लिए नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतः जहां खरां राहत मिलेगी, वहाँ चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बोझ के समान है। ध्यान रहे कि नेशनल इंडेप्रेस अकादमी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 73 प्रतिशत लोगों के पास चिकित्सा बीमा नहीं है। इतना ही नहीं, देश में चिकित्सा बीमा का प्रीमियम 25 से 30 प्रतिशत लोग अपने चिकित्सा बीमा का नवीनीकरण नहीं करता पाते। बुजुर्गों को चिकित्सा बीमा का प्रीमियम के लिए प्रतिवर्ष 12 से 15 हजार रुपये देने पड़ते हैं जो महांग होने के कारण उनके लिए संभव नहीं होता। ऐसे में चिकित्सा बीमा लेने वाले लोगों से प्रीमियम पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूल करना सरकार के लिए नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतः जहां खरां राहत मिलेगी, वहाँ चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बोझ के समान है। ध्यान रहे कि नेशनल इंडेप्रेस अकादमी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 73 प्रतिशत लोगों के पास चिकित्सा बीमा नहीं है। इतना ही नहीं, देश में चिकित्सा बीमा का प्रीमियम 25 से 30 प्रतिशत लोग अपने चिकित्सा बीमा का नवीनीकरण नहीं करता पाते। बुजुर्गों को चिकित्सा बीमा का प्रीमियम के लिए प्रतिवर्ष 12 से 15 हजार रुपये देने पड़ते हैं जो महांग होने के कारण उनके लिए संभव नहीं होता। ऐसे में चिकित्सा बीमा लेने वाले लोगों से प्रीमियम पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूल करना सरकार के लिए नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतः जहां खरां राहत मिलेगी, वहाँ चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बोझ के समान है। ध्यान रहे कि नेशनल इंडेप्रेस अकादमी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 73 प्रतिशत लोगों के पास चिकित्सा बीमा नहीं है। इतना ही नहीं, देश में चिकित्सा बीमा का प्रीमियम 25 से 30 प्रतिशत लोग अपने चिकित्सा बीमा का नवीनीकरण नहीं करता पाते। बुजुर्गों को चिकित्सा बीमा का प्रीमियम के लिए प्रतिवर्ष 12 से 15 हजार रुपये देने पड़ते हैं जो महांग होने के कारण उनके लिए संभव नहीं होता। ऐसे में चिकित्सा बीमा लेने वाले लोगों से



फिर सर्वर फेल, नहीं हो सका 'मुख्यमंत्री मंड़ियां सम्मान योजना' के लिए आवेदन

जीप सदस्य राजू मेहता ने किया शिविर का अवलोकन, जतायी नाराजगी

आजाद सिपाही संवाददाता

हुसैनाबाद। झारखंड सरकार की महत्वकांडी योजना 'मुख्यमंत्री मंडियां सम्मान योजना' की शुरूआत हो चुकी है। इस बाबत हुसैनाबाद में शिविर से जगह-जगह शिविर भी लगाया जा चुका है। लेकिन लगातार सर्वर फेल होने के कारण कार्य योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। बताएं चलें कि राज्य सरकार इस योजना का लाभ 21 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की योग्य महिलाओं को देने के लिए उनके खाते में प्रति माह सीधे 1000 रुपये भेजने वाली है। मुख्यमंत्री दीपंत सोरेन हर गतिविधि की जानकारी अपने सोशल हैंडल के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं,



शिविर में फॉर्म भरवाने की कोशिश करती महिलाएं।

पहुंच भी रही है। लेकिन किसी भी शिविर में एक दिन में 10 लाखुओं का कार्म भरने की सुचा नहीं मिलती है। क्योंकि नेटवर्क व सर्वर की सम्पत्ति लगायत बनी हुई है। उधर, शिविर को हुसैनाबाद उत्तरी जीप सदस्य राजू मेहता ने अपने भारी संख्या में लाभुक महिलाएं

कर जायजा लिया। उन्होंने बताया कि देवरी कला व देवरी खुद पंचायत में अभी तक साइट्स नहीं खुला है। महिलाएं अपनी दैनिक के चक्कर लगा रही हैं। कहा कि सरकार ने बिना किसी तैयारी के आनन्-फानन में इस योजना को लागू करा दिया। जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। कहा कि शिविर में काई अधिकृत अधिकारी या नोडल अधिकारी नहीं हैं और ऑपरेटर के भरोसे सिस्टम को ठीक कराया जा रहा है। वरीं, तरफ भरने की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वह लॉलीपॉय जैसी योजना बन कर रह जायेगी।

तकी रिजवी बने हुसैनाबाद इमामबाड़ा के नये मोतवल्ली



हुसैनाबाद (आजाद सिपाही)। तकी रिजवी को हुसैनाबाद बक्फ वसीला बेगम इमामबाड़ा का नया मोतवल्ली बनाया गया है। विदेश से कि गत दिनों हसैन जैदी ने घेरे लू व्यस्तता का हवाला देकर मोतवल्ली के पद से इसीफा दे दिया था। इसके बाद समाज के लोगों ने बैठक कर अपाले मोतवल्ली का नाम सुझाया। बैठक में उपरित्थ बबूने ने तकी रिजवी का नाम प्रस्तावित किया। जिसका सभी ने नायब किया। जबकि दूसरा नाम अमीन मिर्जा के रूप में आया। लोगों की मंजूरी के बाद उन्हें नायब मोतवल्ली चुना गया। इसलामिक विद्वान हजरत मौलाना सैयद मुस्तफ़ी रज़ा, असरद आलम अब्बास, फिरेज घ्यारे हुसैन, गजफर हुसैन अली, मुर्तजा हुसैन रहेन मिर्जा, मिर्जा जावेद, सैयद फजल हुसैन, निहाल मिर्जा आदि ने बधाई दी।

घासीदाग पंचायत के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर किया मुखिया का घेराव



सड़क की मांग को लेकर मुखिया का घेराव करते ग्रामीण।

सड़क के लिए सांसद से लेकर पंचायत के लोगों ने जोड़वारे की मांग आवाज दिया। ग्रामीणों ने बुजाओं के बाद घेराव हटाया गया। इस दौरान ग्रामीण सड़क नहीं तो बोट नहीं का नाम लगा रहे थे। ग्रामीणों का कहना था कि सड़क औंपुल के आधार में घासीदाग पंचायत बरसात में एक टापू की तरह हो गया है। पंचायत का संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालय से टूट चुका है। इनका ही नहीं मांगों को मेरा समर्थन है। पंचायत को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए कम सक तिलोमीटर लंबी सड़क बनवानी होगी। इन्हीं लंबी

सड़क के लिए पंचायत के पास अपना कोई मर नहीं है। सड़क निर्माण के लिए पलामू सांसद विष्णु दयाल राम और विधायक रामवंद्र चंद्रवंशी से मिलकर कई बार जापन दिया। मुख्यमंत्री तक से निकलने का कोई रासात होता है तो सांसद और विधायक का आवास घेराव करते हैं। इसके अनुपुल के आधार में घासीदाग पंचायत बरसात में एक टापू की तरह हो गया है। पंचायत का संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालय से टूट चुका है। इनका ही नहीं मांगों को मेरा समर्थन है। पंचायत को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए कम सक तिलोमीटर लंबी सड़क बनवानी होगी।

संवेदक की लापरवाही से ग्रामीण परेशान, दरवाजे पर भरा घुटने तक पानी



ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान कुछ ग्रामीणों के इशारे पर

संवेदक द्वारा मनमानी की गई, जो अब परेशानी का सबब बना हुआ है। सड़क पर जलजमाव के कारण फिसलन उत्पन्न हो गयी है, जिससे वहाँ से अपने जाने वाले फिसल कर गिर रहे हैं। ग्रामीणों ने सप्तस्या का हल निकालने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाया है।

संवेदक द्वारा मनमानी की गई, जो अब परेशानी का सबब बना हुआ है। सड़क पर जलजमाव के कारण फिसलन उत्पन्न हो गयी है, जिससे वहाँ से अपने जाने वाले फिसल कर गिर रहे हैं। ग्रामीणों ने सप्तस्या का हल निकालने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुपये का बजट तय कर दिया है।

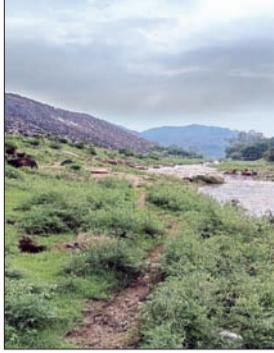
आइसीसी ने चैपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 544 करोड़ रुप

નિયમોની અનદેખી વાળોની જાન જોખિમ મંડાલકર કાર્ય કર રહી આઉટસોર્સિંગ કંપનીઓનું

સંયાદ કુમાર

ધનબાદ (આજાદ સિપાહી)

આઉટસોર્સિંગ કંપનીઓની મનમામી ચરમ પર હૈ। નિયમોની અનદેખી કરનારી ઇનેક્ટ લિએ આમ બાત હૈ એન્યુર્વારા કિ સરસ્યા હોય વાયુ-જલ પ્રદૂષણ ઇન પર કોઈ પ્રભાવ નહીં પડતા। ગરીબોની જીવન તક ખેલવાડી કરને સેપણે નહીં હત્તે। બતાતે ચલે કે એસટેઝી એવં એસેન્ટાર કંપનીઓની ગોપાલીચક મંડિસ્થ હૈ, જે એક-દૂસરી સીમા સેપણી હૈ। યેલો નિયમોની સેપણીઓની સંબાલિત કરને કીં બાત તો કરતે હૈ, લોકીન નિયમોની કી ઘણિયા ભી હોય લોગ ઉડા રહે હૈનું। બતાતે ચલે કે એસટેઝી આઉટસોર્સિંગ કોન્ટો કાર્ય કરતે નો મહીને સે અધિક કાસમ્ય બીત ચુકા હૈ। દો સાલ કી લોજ પર ઇસ કંપની કો લોજ પર 1709 પેડે



કંપનીની કેબલ સે જુડ્ગિયા નદી ગુજરી હૈ।

જિસમાં લગાતાર બ્લાસ્ટિંગ કે કારણ ટૂટ ગયા થા।

બાંધીની ભૂખ્યાં આદિ કિંદી ઘર એસે હૈનું।

જો દેવી બ્લાસ્ટિંગ સે પેરેશન હૈ।

બાંધીની મજદૂરી કર અપણા પેટ

પાલને વાલે લોગોનો શિફિંગ કે હૈ।

મજદૂરી કર અપણા પેટ પાલને

જગહ રહ્યેની કી બાત ભી હુંદું થી।

પર નિયમોની કી અનરખી કર આઉટસોર્સિંગ કંપનીઓની અપણે કામ કોણ અંજામ દેને મેં લોગ હૈ।

તત્કાલ સેવા કે નામ પર

ગારીબીનામે રહ્યેની કી વ્યવસ્થા કી

ગઈ, પર વહાં ભી રહ્યેની જગહ

કાટેનો કા પરમિશન લિયા થા।

પર અંધાધૂંધ રૂપ સે કિતને હજાર

પેંડોનો કો કાટ દ્વારા ઇસકા કાર્ય

લેખા-જાયા નહીં હૈ। ડેંપર જાન

સે નિવાસ કરને વાલે ગીરીબી

મજદૂરીનો કો સ્થાનાતંત્રણ કર દૂસરી

જગહ રહ્યેની કી બાત ભી હુંદું થી।

પર નિયમોની કી અનરખી કર આઉટસોર્સિંગ કંપનીઓની અપણે

કામ કોણ અંજામ દેને મેં લોગ હૈ।

તત્કાલ સેવા કે નામ પર

પણ રજવાર, વિકાસ રજવાર,

દાંચ સેવા કે નામ પર

ગારીબીનામે રહ્યેની કી વ્યવસ્થા કી

ગઈ, પર વહાં ભી રહ્યેની જગહ

કરેણે હૈ। ઇસે રેંડ જોન ભી ઘોસિત કર દ્વારા ગયા

હૈ। બતાતે ચલે કે ઇસ કંપનીની

કામ કરતે હું હોય હુંદું એક સાલ

બીત ચુકે હૈનું।

કંપનીની ભી તીવીન

સાલ કા લીજ મિલા હૈ જિસમાં

8.97 લાખ ટન કોબલા કા

રાઠાવાન કુદાંસ રહેણી હૈ।

જાન હોય હુંદું એક સાલ

બીત ચુકે હૈનું।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

દ્વારા ગયા હૈ।

અને રેંડ જોન ભી ઘોસિત કરેણે

</div

